THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

श्री राघव चड्ढा : सर, यह दर्द फ्लाइट में चढ़ने से लेकर फ्लाइट से उतरने का था। मैं अंत में चार पंक्तियां सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज इस देश के आम नागरिक आम यात्री का दर्द इन पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा-

"कहीं हैं लम्बी लाइनें ,कहीं चेकइन से पहले काउंटर बंद,
कहीं स्लो चल रहा है सर्वर ,कहीं इंटरनेट है मंद,
महंगी टिकट के बाद भी यात्रा की कोई गारंटी नहीं,
आपका सामान चाहे टूटे ,चाहे फूटे कोई वारंटी नहीं,
जो हाल है बस अड्डों का, वही तस्वीर आती है एयरपोर्ट से,
चाय हो या समोसा ,नहीं मिल रहा पाँच सौ रुपये के नोट से,
रोज़ फ्लाइट्स बंद हो रही हैं धमकी ,बम ,विस्फोट से,
कब तक आम आदमी मरता रहेगा एयरपोर्ट की छत गिरने की चोट से,
जनता की मुश्किलें तो पल भर में मिट जाएं,
अगर सरकार को फुर्सत मिल जाए चुनाव या वोट से।"

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Members, may I have your attention, please? Hon. Members, the debate will continue tomorrow. We will now take up Special Mentions. माननीय श्री संजय कुमार झा जी। संजय कुमार झा साहब के पास स्पेशल मेंशन पहुंचा नहीं है। हम नेक्स्ट प्वाइंट पर चलते हैं, तब तक उनके पास स्पेशल मेंशन पहुंच जाएगा। माननीय श्री नरेश बंसल जी। Hon. Members, those who are leaving, may kindly leave silently. जो लोग जाना चाहते हैं, वे कॉरिडोर्स में न रहें। जिन लोगों को जाना है, वे चले जाएं, जिन लोगों को रुकना है, वे रुकें, but do it silently, in an orderly fashion. Thank you.

SPECIAL MENTIONS

Demand to fix rates of various treatments and procedures in private hospitals for general public on the lines of CGHS

श्री नरेश बंसल (उत्तराखंड) : महोदय, देश में निजी क्षेत्र के अस्पतालों की इलाज दरों में घोर असमानता है। निजी अस्पतालों के महंगे इलाज के एवज में बीमार व्यक्ति को भारी-भरकम बिल चुकाना पड़ता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसका एक मुख्य कारण निजी अस्पताल की दरों पर कोई नियंत्रण न होना है। निजी अस्पताल मरीजों से इलाज के एवज में मनमाने तरीके से धनराशि वसूलते हैं, इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी के अभाव में जनता

इलाज के लिए मनमानी राशि देने हेतु बाध्य है। 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' एवं 'आयुष्मान योजना' मील का पत्थर साबित हुई है, जिसने गरीब को अच्छा इलाज व राहत दी है।

महोदय, मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि देश में संचालित मेडिक्लेम कंपनियां अपने पॉलिसी होल्डर को सस्ती दरों पर इन्हीं निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए समझौता करती हैं, जिनकी दर काफी कम है। इसी प्रकार सीजीएचएस की दर भी है। जब छोटी-छोटी मेडिक्लेम कंपनियां, निजी अस्पतालों से समझौता करके सस्ती दरों पर इलाज करा सकती हैं, तो सरकार क्यों निजी अस्पतालों के लिए दर तय नहीं करती, जिसके आधार पर जनता सस्ती दरों पर इलाज करा सके?

महोदय, सरकार से मेरी मांग है कि निजी अस्पतालों में इलाज हेतु सभी चीजों की दर तय की जाए, जिसके आधार पर आम नागरिक निजी अस्पतालों से सस्ती दरों पर इलाज करा सके।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Naresh Bansal: Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. Sikander Kumar (Himachal Pradesh), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu) and Shri Rambhai Harjibhai Mokariya (Gujarat).

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय श्री संजय कुमार झा जी।

Demand for establishment of Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) Centre in Bihar

श्री संजय कुमार झा (बिहार) : महोदय, बिहार से उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों जैसे मखाना और लीची का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2023-24 में केवल मखाना का निर्यात लगभग 300 करोड़ रुपये का था। इसके अलावा, बिहार में भागलपुरी शाही लीची, जर्दालू आम, कतरनी चावल और मगही पान जैसे GI-टैग वाले कृषि उत्पादों की अपार क्षमता है। बिहार के किसान और व्यापारी वर्तमान में वाराणसी में स्थित Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) केंद्र के माध्यम से कृषि निर्यात करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिहार में पटना, दरभंगा और गया एयरपोर्ट निरंतर परिचालन में हैं, और जल्द ही पूर्णिया एयरपोर्ट भी पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। यह एयरपोर्ट बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात को और आसान बनाएगा।

इस संदर्भ में, मेरा सरकार से अनुरोध है कि बिहार में APEDA केंद्र की स्थापना पर विचार करे। इस केंद्र की स्थापना से बिहार के प्रीमियम कृषि उत्पादों जैसे मखाना, लीची और अन्य GI-टैग उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, यह केंद्र मूल्य वर्धित प्रसंस्करण, किसानों को बेहतर प्रशिक्षण और बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक होगा। इससे राज्य के कृषि क्षेत्र को वैश्विक बाजारों में बेहतर पहचान मिल सकेगी और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।